Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X, General Impact Factor : 2.5442, Volume 08, No. 02, April, 2018, pp. 484-485

भारत में आर्थिक दृष्टि से महिला सशक्तिकरण

प्रतिमा खटुमरा*

''यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा महिलाओं का विकास होने पर समाज का विकास स्वतः हो जायेगा'' –जवाहर लाल नेहरु

आज का समय महिला सशक्तिकरण का है। जिधर नजर दौड़ाइए, आपको महिलाओं की व्यापकता, सामर्थ्य और कुशलता के दर्शन हो जाएँगे। स्त्री–शिक्षा, स्त्री–अधिकार, पुरुषों के साथ बराबर की कदमताल, अपने कर्त्तव्यों के प्रति चेतना, आपको सर्वत्र दृष्टिकोण होगी। हो भी क्यों न, आज शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, खेल, व्यवसाय, प्रबंधन, गृह–निर्माण, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मोबाइल, इंटरनेट कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर, प्रशासन, शिक्षण, आध्यात्म, मीडिया, पत्रकारिता, सेना, मंत्रिमण्डल सब ओर महिलाएँ ध्वजवाहिका बनी खड़ी नजर आती है। वह दिन लद गए, जब स्त्री को घर की चाहरदीवारी में कैद करके रखना, पुरुष अपनी शान और अधिकार समझता था। आज हिमालय पर महिलाएँ झण्डे गाढ़ रही हैं। वर्तमान दौर में महिलाएँ जितनी अपने कर्त्तव्यों के प्रति सचेत हुई है, उतनी ही अपने अधिकारों के प्रति जागरुक। डॉ. दंगल झाल्टे के अनुसार, ''स्वातन्त्रयोत्तर नारी अपने जीवन के प्रति गहनता से सोचने लगी है। वह पति से गुलामी नहीं बराबरी का, सहधर्मिणी का रिश्ता चाहती है। परिवार तथा सभ्यता की बागडोर अपने हाथों में लेकर भी वह विश्व के उन्मुक्त प्रांगण में विचरण की आकांक्षा लिए हुए हैं।'' महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिला वर्ग की क्षमता या शक्ति का विकास करना है। जिससे वे अपना जीवन का निर्वाह अपनी इच्छानुसार कर सकने में सक्षम हो सके। अर्थात महिलाओं की आर्थिक शक्ति का विकास कर उन्हें अपनी क्षमता का विकास कर उन्हें अपनी क्षमता का एहसास कराना उनमें आत्म–विश्वास एवं स्वीकार्यता विकसित करना ताकि महिलायें समाज एवं देश के सर्वपक्षीय विकास में शामिल हैं। महिलाओं को समाज में समान दर्जा प्रदान कर सशक्त बनाने के लिये आजादी के बाद पिछले छःदशकों में सरकारी एवं गैर–सरकारी दोनों ही स्तर पर निरंतर प्रयास किये गये हैं।

समाचार पत्र ''जागरण ब्यूरो'' नई दिल्ली मे प्रकाशित समाचार के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को वक्त की जरुरत बताते हुए कहा है कि दुनिया और विशेषकर भारत में अभी भी महिलाएं कई तरह का लिंग आधारित भेदभाव झेलती है। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं का वास्तविक सशक्तिकरण तभी होगा, जबकि वे उन्हें प्राप्त अधिकारों का लाभ उठाएं और साथ ही आर्थिक रुप से सशक्त हो। महिला सशक्तिकरण के लिए जरुरी है उनका आर्थिक सशक्तिकरण। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसेः–

- सदियों से महिलाओं की आवज दबी हुई है। अगर वो आर्थिक रुप से सशक्त होंगी, तो समाज में भी उनकी बात सुनी जाएगी। क्योंकि समाज में आर्थिक रुप से सबल इंसान को ज्यादा महत्व दिया जाता है।
- आर्थिक रुप से सशक्त होने पर महिलाओं की निर्भरता पुरुषों पर से खत्म हो जाएगी, ऐसे में उन्हें अपने अधिकारों के लिए पुरुषों का मुँह नहीं ताकना पड़ेगा।
- महिलाएं कमाएं हुए पैसे या परिवार के किसी अन्य स्त्रोत से मिले पैसे को बच्चों के भरण पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करती हैं। इसका बेहतरीन उदाहरण केरल है। ऐसे मे अगर महिलाओं के आर्थिक रूप से सशक्त होने पर बच्चो के भी विकास में मदद मिलेगी।
- आर्थिक रूप से सशक्त महिलाएँ आत्मविश्वास से पूर्ण होती है। ऐसे मे उनकी सामाजिक सुरक्षा उनके अधिकारो की लडाई वो खुद लड सकती है। जो महिला सशक्तिकरण कि दिशा मे कारगर साबित हो सकता है।
- हाल ही मे विश्व आर्थिक मंच कि ओर से जारी ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में लैंगिक समानता के मामले मे भारत को 87 वां स्थान मिला है, जिसमें आर्थिक तौर पर असमानता को सबसे बडी चुनौती माना गया है। यानी बिना आर्थिक खाई को पाटकर हम लैंगिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त नही कर सकते है।

वस्तुतः इक्कीसवीं सदी महिला सदी है। वर्ष, 2001 महिला सशक्तिकरण वर्ष के रुप में मनाया गया। हालांकि ये काम बिना समाज और सरकार के प्रयासों से नही हो सकता है। सरकार द्वारा इस दिशा में कई कदम उठाये गये है, जैसेः–

* सहायक आचार्य– हिन्दी, स.ध.राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर, राजस्थान।

- 2001 में सरकार ने ''महिला उत्थान नीति'' बनाई है जिसके तहत उनके आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर कई कदम उठाये गये है।
- महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टैंड अप इंडिया जैसी कई योजनाएं चलाईं गईं, जिसके तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग में महिलाओं को आगे आने का मौका मिल रहा है।
- प्रधानमंत्री जनधन योजना और महिला बैंक जैसे कदम उठाकर महिलाओं की पहुंच बैंक तक आसान की गई, ताकि वो अपनी कमाई को सुरक्षित रख सकें।

हॉलांकि अभी भी इस दिशा में कई कदम उठाए जाने बाकी है। सबसे जरुरी है महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर समाज के एक बड़े हिस्से की सोच बदले।

महिला सशक्तिकरण में मुद्रा योजना की भूमिका

देश की महिलाओं को आर्थिक रुप से मजबूत बनाने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है। जिसमें देश के सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जिससे कि महिलाएं भी कारोबार के क्षेत्र में बढ.चढ़ कर हिस्सा लें रही हैं। महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना(माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी) काम कर रही है सरकार ने, छोटे कारोबारियों को व्यावसाय में बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुद्रा बैंक योजना की घोषणा की है, जिसकी शुरुआत वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट (2015–2016) में 20 हजार करोड़ कोष और 03 हजार करोड रुपए साख गारंटी रखकर की है। इस योजना का उद्देश्य उचित ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के रुप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। खास बात यह है कि कर्ज लेने वालों को एक मुद्रा कार्ड भी मिल रहा है जिसे वे जरुरत पड़ने पर क्रेडिट कार्ड की तरह इस्तेमाल कर सकती है। इस कार्ड के जरिये अचानक जरुरत पड़ने पर दस हजार रुपये तक निकाले जा सकते हैं। मुद्रा योजना का वास्तविक उद्देश्य रोज़गार प्रदान करना है। परन्तु इसका अर्थ मात्र रोज़गार उत्पन्न करना ही नहीं हैं बल्कि लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना भी है। लघु उद्यमों और नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ ही मुद्रा योजना रोजगार मुहैया करने के लिए सरकार की योजनाएं ढाँचे का एक महत्वपूर्ण आयाम है। महिलायों के हित में यह में यह मुद्रा स्कीम काफी फायदेमंद है। इस योजना का लाभ किसी बैंक से लिया जा सकता है। सरकार ने यह योजना ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में कारोबार करने वाली महिलाओं को देखते हुए बनाया है। जिसमें महिलाओं को 50 हजार रुपए से 10 लाख रुपए का लोन मुहैया आसानी से बिना गारंटर के मिल रहा है। मुद्रा बैंक के अन्तर्गत महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को ऋण देने में प्राथमिकता दी जा रही है महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये योजना बहुत ही सफल और लोकप्रिय साबित हो रही है।

इस योजना में महिला उद्यमियों के लिए अलग से महिला उद्यम निधि नाम की विशेष योजना है। इसके तहत सभी तीन श्रेणियों (शिशु, किशोर, व तरुण) में महिला को लोन मिल रहा है, इस योजना के तहत पापड़, अचार आदि का व्यापार कर रही कारोबारी महिलाओं को भी इस बैंक की ओर से ऋण प्रदान किया जा रहा है ताकि वो छोटे स्तर से अपना कारोबार शुरु कर सकती है और दूसरों को भी रोज़गार उपलब्ध करा सकती है। भारत सरकार द्वारा शुरु की गई मुद्रा योजना, नए उद्यमों को शुरु करने के लिए महिलाओं को ऋण प्रदान करके उन्हें सशक्त बना कर उनकी स्थिति में सुधार करने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है। सामाजिक बदलाव को बढ़ावा देने वाले विकास में महिला और पुरुष दोनों की भूमिका हैं। आज यह महसूस किया जाने लगा है कि महिलाओं में स्वास्थ्य, शिक्षा, कमाने के मौके और राजनैतिक भागीदारी की क्षमता विकसित करने में महिला सशक्तिकरण और आर्थिक सशक्तिकरण एक–दूसरे से जुड़े हुए हैं। महिला और पुरुष के बीच बराबरी लाने के लिए सिर्फ आर्थिक विकास ही काफी नहीं हैं। महिला और और पुरुष के बीच बराबरी लाने के लिए नीतिगत कार्यवाही भी जरुरी हैं। महिलाओं को आर्थिक भागीदारी में बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक कदम उठाने होंगें।

नारी तुम केवल श्रद्धा हो!
विश्वास रज नभ पग तल में।
पीयूष स्त्रोत सी बहा करो।
जीवन के सुन्दर समतल में।।

भारतीय संस्कृति की पूरोधा भारतीय नारी सृष्टि की मूल चेतना है। कई गुणों की खान होने के साथ–साथ वर्तमान में उसने आधुनिक जीवन की विसंगतियों के बीच में व्यक्तित्व को उभारने की कोशिश की है। आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और आर्थिक सक्षमता ही उसका मूल मंत्र है।

सन्दर्भ ग्रन्थः–

- डॉ. दगंल झाल्टे : नये उपन्यासों में नये प्रयोग, पृष्ठ सं. 90।
- जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली।
- जयशंकर प्रसाद, कामायनी।

♦❐♦